

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 171/2020

पुष्करलाल पुत्र भंवर लाल श्रीमाली, उम्र लगभग 46 वर्ष, बड़गांव, पोस्ट
ढोल, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर।

-----अपीलकर्ता

बनाम

प्रशासनिक अधिकारी, महाराणा प्रताप स्मारक, उदयपुर, मोती मगरी,
उदयपुर

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री सुमित सिंघल

माननीय न्यायाधिपति संगीत लोढा
माननीय न्यायाधिपति रामेश्वर व्यास

आदेश

15/09/2020

रिपोर्टबल

1. यह इंट्रा कोर्ट अपील इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.19 के विरुद्ध निर्देशित है, जिससे श्रम न्यायालय, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.19 से व्यथित अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका खारिज कर दी गई है।
2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.12.07 के माध्यम से, अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद निम्नलिखित शर्तों के तहत श्रम न्यायालय, उदयपुर को निर्णय के लिए भेजा गया था:

"क्या प्रार्थी श्रमिक की परिभाषा में आता है, यदि हां, तो क्या श्रमिक श्री पुष्कर श्रीमाली पुत्र श्री भंवरलाल श्रीमाली निवासी बडगांव, तहसील गोगुन्दा, हाल मुकाम 42 कर्मशील मार्ग, चांदपोल बाहर, सिरोही वाडा, उदयपुर द्वारा श्री सुभाष श्रीमाली, महासचिव, लघु उद्योग कामगार यूनियन, उदयपुर को नियोजक प्रसाशनिक अधिकारी, महाराणा प्रताप

स्मारक समिति, मोती मगरी, उदयपुर द्वारा दिनांक
31.07.2005 से सेवा पृथक कर दिया जाना उचित
एवं वैध है ? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत को
पाने का अधिकारी है ?"

3. अपीलकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष अपने दावे का बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसने 1.4.02 को चौकीदार/पुजारी के रूप में 2500/- रुपये प्रति माह के निश्चित वेतन पर प्रतिवादी के यहां रोजगार में प्रवेश किया था। हालाँकि, उनकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताए 31.7.05 से समाप्त कर दी गईं। संक्षेप में, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामला यह था कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी कर ली थी और इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "1947 का अधिनियम") की धारा 25 एफ के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना उनकी सेवाओं की समाप्ति अमान्य और शून्य है।

4. प्रतिवादी द्वारा दावे का प्रतिवाद दायर करके यह तर्क दिया गया कि पुजारी के काम के लिए अपीलकर्ता की सेवाएं ठेकेदार एम/एस.आर.एस.डी.एंटरप्राइजेज, उदयपुर द्वारा प्रतिवादी को उपलब्ध कराई गई थीं। अपीलकर्ता ठेकेदार के नियंत्रण में काम कर रहा था और ठेकेदार द्वारा उसे वेतन भी दिया जा रहा था। एक प्रारंभिक आपत्ति

उठाई गई थी कि अपीलकर्ता को नियोजित करने वाला ठेकेदार एक आवश्यक पक्ष है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत था, चूंकि पुजारी 'कर्मचारी' की परिभाषा में नहीं आता है और मंदिर 'उद्योग' की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए 1947 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

5. रिकॉर्ड पर साक्ष्यों पर उचित विचार करने के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मंदिर 'उद्योग' की परिभाषा में नहीं आता है और अपीलकर्ता को पुजारी के रूप में नियोजित किया जाना 'कर्मचारी' की परिभाषा में नहीं आता है और परिणामस्वरूप, आक्षेपित पुरस्कार द्वारा उनके दावे को खारिज कर दिया।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसे चौकीदार-सह-पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए, श्रम न्यायालय का निर्णय जो इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अपीलकर्ता केवल पुजारी के रूप में कार्यरत था, गलत है।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर उचित विचार करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रिकॉर्ड पर लाए गए किसी भी सबूत के अभाव में यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता ने पुजारी के अलावा कोई अन्य कार्य किया है, याचिका में यह कहा गया कि

अपीलकर्ता ने चौकीदार-सह-पुजारी के रूप में काम किया था, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता चौकीदार-सह-पुजारी के रूप में कार्यरत था और वह मुख्य रूप से चौकीदार के कार्य कर रहा था। प्रतिवादी के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी पत्र दिनांक 6.12.03 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जाहिर तौर पर, अपीलकर्ता को रात के समय मंदिर की रक्षा करने का निर्देश दिया गया था और इस प्रकार, रात के समय मंदिर की रक्षा करना अपीलकर्ता के कर्तव्य का हिस्सा था, श्रम न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष, जिसकी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई कि अपीलकर्ता केवल पुजारी के रूप में कार्यरत था, प्रथम दृष्टया गलत और विकृत है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी समिति द्वारा नियोजित किया गया था, इसलिए, यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता को विशेष रूप से मंदिर में नियोजित किया गया था, जो 'उद्योग' की परिभाषा में नहीं आता है, गलत है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि साईं भक्त समाज बनाम दुर्गा प्रसाद में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भी: 11.9.06 को निर्णयित डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3731/04 को श्रम

न्यायालय और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में नहीं सराहा गया, जिसके परिणामस्वरूप गलत निष्कर्ष निकाला गया।

9. हमने विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

10. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने दिनांक 1.4.02 (अनुलग्नक 4) के आदेश के तहत नियुक्त होने पर प्रतिवादी के रोजगार में प्रवेश किया, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जैसा कि दावा किया गया है, अपीलकर्ता को अस्थायी आधार पर तीन महीने की अवधि के लिए 'पुजारी' के पद पर रु. 2500/- प्रति माह के निश्चित वेतन पर नियुक्ति दी गई थी, न कि 'चौकीदार-सह-पुजारी' के पद पर, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता गिरधर गोपाल मंदिर में 'सेवा पूजा' करेगा और मंदिर परिसर में रहेगा। अनुलग्नक-5 (श्रम न्यायालय के समक्ष उदाहरण 2 के रूप में प्रदर्शित) के अनुसार, पुजारी द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें दावे के अनुसार चौकीदार के कर्तव्य भी शामिल नहीं हैं। केवल इसलिए कि, अपीलकर्ता और अन्य पुजारियों को रात में मंदिर परिसर में रहने के लिए निर्देशित किया गया था, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता को चौकीदार के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए

बनाया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ही माना है कि अपीलकर्ता को आवास के माध्यम से मंदिर परिसर में रहने का निर्देश अपीलकर्ता की स्थिति को पुजारी से अलग नहीं कर सकता है।

11. श्रम न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए साईं भक्त समाज के मामले (सुप्रा) में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि 1947 के अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत कवर होने के लिए, एक श्रमिक को वह माना जाता है जो कोई भी मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य करता है, जबकि पुजारी द्वारा पूजा धार्मिक हाइमन और भजन और आरती के अपने ज्ञान का एक अनुप्रयोग है, जिसे उसे मंदिर में सुनाना है, जिसे किसी भी दृष्टि से 1947 के अधिनियम की धारा 2(एस) में निर्दिष्ट कार्य नहीं माना जा सकता है और तदनुसार, यह माना जाता है कि पुजारी एक कर्मकार नहीं है।

12. साईं भक्त समाज के मामले (सुप्रा) में निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लक्ष्मी नारायण शास्त्री बनाम श्री संतान धर्म सभा लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट: डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3426/11, 20.05.

11 को निर्णय के बाद आगे बढ़ाया गया है।

13. यह सच है कि किसी कर्मचारी का पदनाम उसे 1947 के अधिनियम की धारा 2(एस) में निर्धारित 'कर्मचारी' की परिभाषा के

अंतर्गत लाने के लिए निर्णायक नहीं है, लेकिन फिर, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई कर्मचारी 'कर्मचारी' की परिभाषा में आता है या नहीं, परीक्षण यह है कि उसे सौंपा गया मुख्य कार्य क्या है। यदि वह उसे सौंपे गए मुख्य कार्य के सहायक या आकस्मिक रूप में कुछ मैनुअल काम करता है, तो ऐसे कर्मचारी को 1947 के अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ के तहत 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता है।

14. वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलकर्ता को पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि चौकीदार सह-पुजारी के रूप में, जैसा कि दावा किया गया था और उसे गिरधर गोपाल मंदिर में सेवा पूजा करने का कर्तव्य सौंपा गया था। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलकर्ता को मंदिर परिसर के भीतर आवास प्रदान किया गया और रात में परिसर में रहने की अनुमति दी गई, किसी भी तरह से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उसे चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे उक्त पद के कर्तव्य सौंपे गए थे। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, श्रम न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है अपीलकर्ता को पुजारी के रूप में नियोजित किया जाना 1947 के अधिनियम की धारा 2(एस) के अर्थ में 'कर्मचारी' की परिभाषा के

अंतर्गत नहीं आता था, इसे मनमौजी या विकृत नहीं कहा जा सकता है, जिससे इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इसके अलावा, भले ही यह मान लिया जाए कि प्रतिवादी, अपीलकर्ता का नियोक्ता, पूरी तरह से मंदिर के रखरखाव में संलग्न नहीं है, 1947 के अधिनियम की धारा 2 (जे) में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अपीलकर्ता कर्मकार नहीं होने के कारण, अधिनियम 1947 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं और श्रम न्यायालय के पास उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट विवाद पर फैसला देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

15. उपरोक्त कारणों से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

16. इंद्रा कोर्ट अपील क्षेत्राधिकार में हमारे द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

17. अतः अपील को तत्काल खारिज किया जाता है।

न्यायाधीश, (कुमारी प्रभा शर्मा)

न्यायाधीश, (संदीप मेहता)

(अनुवाद एआई टूल: SUVAS के माध्यम से अनुवादक की मदद से किया गया है)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय का उपयोग वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।